नीति आयोग
(राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान)
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

नया भारत @2022

राज्यपाल सम्मेलन

12 अक्तूबर 2017

राजीव कुमार
उपाध्यक्ष, नीति आयोग

नीति आयोगः भारत परिवर्तन

सतत विकास ही जीवन की विधि है और ऐसा व्यक्ति जो अनुकूल दिखाई पड़ने के लिए अपने धर्म सिद्धांत को बनाए रखने का प्रयत्न करता है सदैव स्वयं को भ्रामक स्थिति में धकेलता है- महात्मा गांधी (नीति आयोग के मंत्रिमंडल संकल्प में उद्धृत)

योजना आयोग

1 पंचवर्षीय योजनाएं

2 निधि वितरक

3 वन साइज फिट्स ऑल मॉडल

1950

जनवरी 2015

नीति आयोग

1 विकेंद्रीकृत, सबसे निचले को ऊपर लाने की कार्यनीति

2 विचार प्रवर्तक

3 टीम इंडियाः सहकारितापूर्ण, प्रतिस्पर्धी संघवाद

विकास: एक जन आन्दोलन

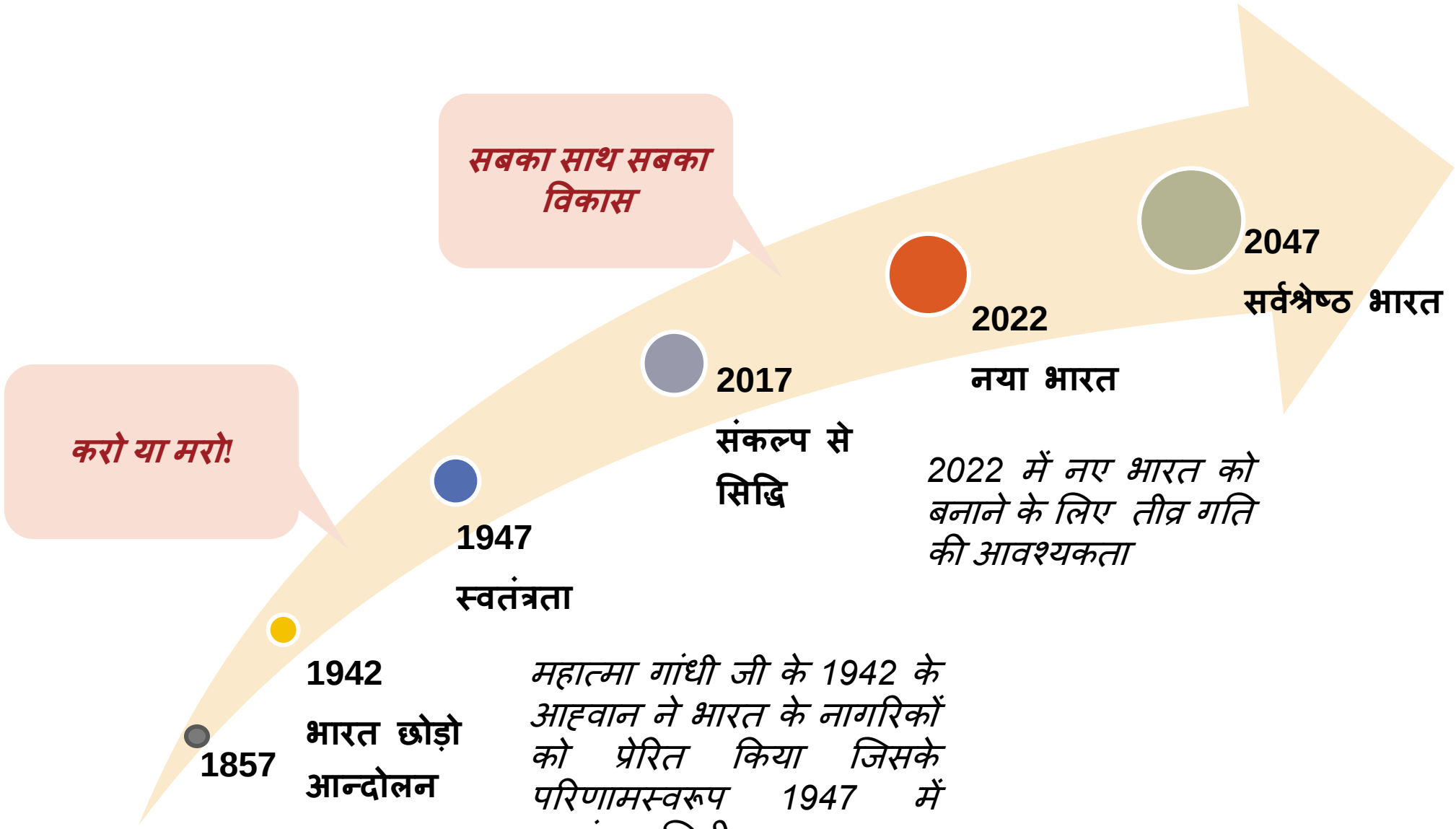

भारत का अद्‌वितीय विकास

- स्वतंत्रता के बाद भारत का विकास विश्व के इतिहास में अद्‌वितीय है।
- भारत के राष्ट्र निर्माताओं ने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन का एक साथ करने का अनूठा विकल्प चुना।
- मानव विकास के इतिहास में ऐसा प्रयास कभी नहीं किया गया।
- इतिहास में कोई भी आधुनिक औद्‌योगिक अर्थव्यवस्था सभी नागरिकों को समान अधिकार देते हुए स्थापित नहीं हुई।
- इतना विशाल सामाजिक परिवर्तन न्यूनतम मानवीय हानी के बिना किसी और देश में नहीं हो पाया।
- हम सभी को इस उपलब्धि पर गर्व होना चाहिए।

नया भारत @ 2022 – संसार के लिए एक आदर्श

- इन तीन परिवर्तनों को सफलतापूर्वक पूरा करके, भारत शेष संसार के लिए एक आदर्श के रूप में उभरेगा।
- **2017-2022: विकास को एक जन आंदोलन बनाना है**
- संकल्प से सिद्धि:

स्वच्छ
स्वस्थ
शिक्षित
सम्पन्न
सक्षम
सुरक्षित

} भारत - 2022

2022 तक देश का संकल्प होना चाहिए किः

गरीबी मुक्त भारत

गंदगी मुक्त भारत

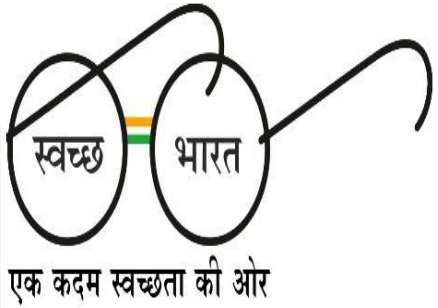

भ्रष्टाचार मुक्त भारत

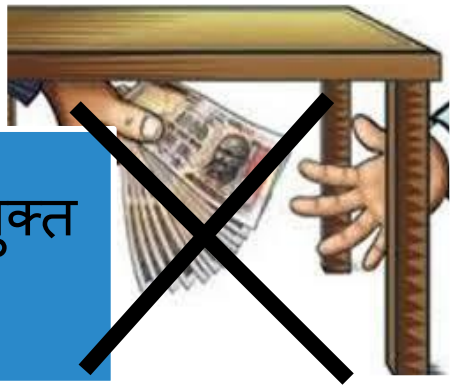

आतंकवाद मुक्त भारत

जातिवाद मुक्त भारत

साम्प्रदायिकता मुक्त भारत

मुक्ति 1: गरीबी मुक्त भारत (1/4)

समावेशी विकास

अंत्योदय

तीव्र आर्थिक विकास

विश्व में अग्रणी फर्म
अनुसंधान और विकास (R&D) पर
अत्यंत जोर
नवप्रवर्तन
तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पारितंत्र

ईओडीबी रैंकिंग में शीर्ष 50 स्थानों में जगह बनाना

कृषि परिवर्तन

किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करना

किसानों को जोखिम-मुक्त करना

गरीबी मुक्त भारत: सामाजिक विकास (2/4)

स्वास्थ्य और पोषण

- पांच वर्ष से कम आयु के एक-तिहाई बच्चे सामान्य से कम वजन और कद के; 50% युवा महिलाएं रक्ताल्पता से ग्रसित
- ***2022 तक कुपोषण मुक्त भारत के लक्ष्य की प्राप्ति***
- *स्वस्थ भारत :* समग्र स्वास्थ्य पर जोर

शिक्षा और कौशल विकास

- *पढ़े इंडिया बढ़े इंडिया*
- 2021 से पीसा में सहभागिता
- 2022 तक उच्चतर शिक्षा के 20 विश्व-स्तरीय संस्थान

महिला सशक्तिकरण

- *बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ*
- सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन

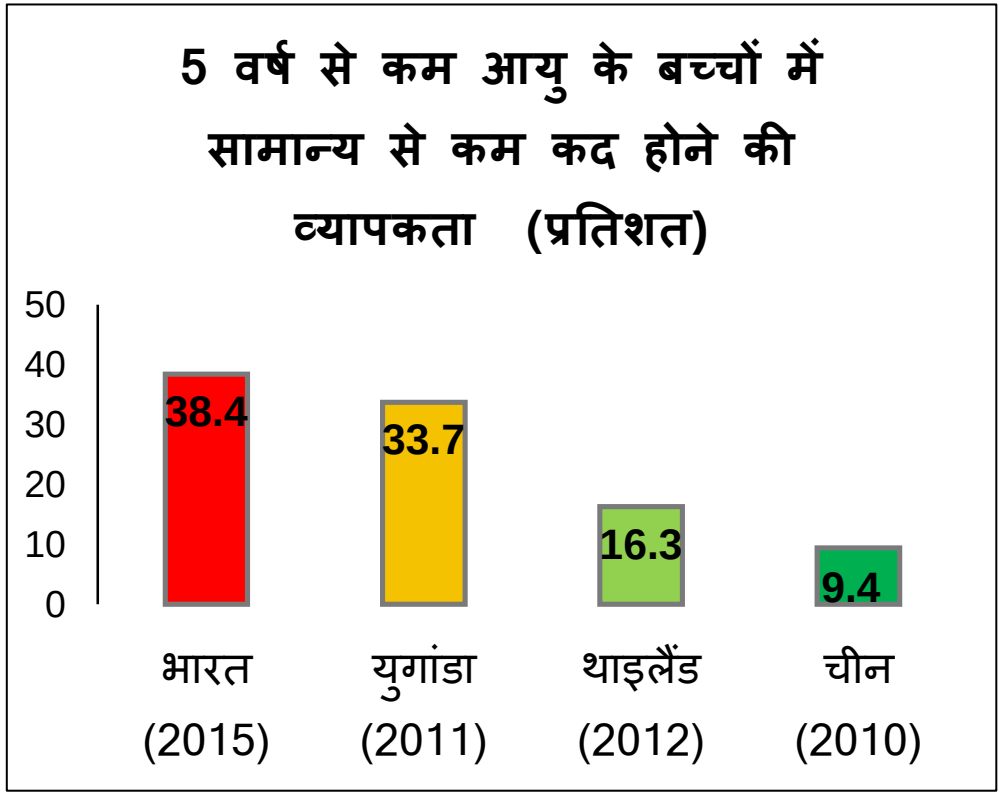

गरीबी मुक्त भारत : मूलभूत ढांचा और संपर्कता (3/4)

- 100 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास; 2022 तक बुलेट ट्रेन
- तीव्र गति रेलवे का चतुर्भुज
- 500 (विशेष क्षेत्रों में 250) से अधिक पर्यावासों वाले सभी गांवों को पीएमजीएसवाई के तहत 2019 तक बारहमासी सड़कों से जोड़ना
- *सागरमाला,* अंतर्देशीय जलमार्ग, नदियों को आपस में जोड़ना
- क्षेत्रीय संपर्कता के लिए *उड़ान* स्कीम
- 'भारतनेट' के तहत 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना

गरीबी मुक्त भारत: विकास के स्तंभ (4/4)

आवास

- *'हाउसिंग फॉर ऑल 2022'* – 2019 तक 1 करोड़ ग्रामीण मकानों और 2022 तक 1.2 करोड़ शहरी मकानों का लक्ष्य

ऊर्जा

- *दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना:* लगभग 2,800 ग्रामों का विद्युतीकरण शेष है
- *'सौभाग्य'* योजना के अंतर्गत दिसम्बर 2018 तक 4 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन देना

वित्तीय समावेशन

- जन धन: 30 करोड़ नए बैंक खाते;
- *'JAM Trinity'*: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से 2 लाख करोड़ रु. से ज्यादा दिए गए

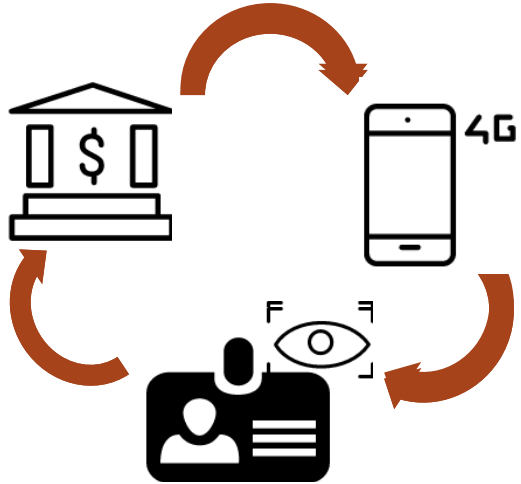

मुक्ति 2: गंदगी मुक्त भारत

- 5 राज्य खुले में शौच की समस्या से मुक्त
- 2 अक्तूबर 2019 यानी गांधी जी की 150वीं जयंती तक भारत खुले शौच की समस्या से मुक्ति
- प्रभाव: खुले में शौच की समस्या वाले ग्रामों की तुलना में मुक्त ग्रामों में बच्चों में अतिसार के मामलों में 46% की कमी

स्वच्छ भारत

- नमामि गंगे - महत्वपूर्ण प्रगति

स्वच्छ नदियां

- 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) क्षमता 175 जीडब्ल्यू
- 2020 तक विद्युत वाहनों की संचयी संख्या 1.5-1.6 करोड़

स्वच्छ ऊर्जा

मुक्ति 3: भ्रष्टाचार मुक्त भारत

विमुद्रीकरण

- 56 लाख नए करदाता जोड़े गए
- 29,123 करोड़ रु. की अघोषित आय का पता लगाया गया और स्वीकार की गई
- 3 लाख शैल कंपनियों का पता लगाया गया और 2.1 लाख शैल कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया गया

जीएसटी

- एक सबसे बड़ा कर सुधार जो भारत में अधिकांश व्यवसायों को औपचारिक रूप दे रहा है
- जीएसटीएन महत्वपूर्ण डेटा एकत्र कर रहा है ताकि कर विवरणियों का विश्लेषण किया जा सके

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)

- *आपका अधिकार, अपने द्वार* –अब तक *2 लाख करोड़ रु. से ज्यादा के संचयी लाभ अंतरण के साथ 57,000 करोड़ रु. की कुल बचत*
- जनधन खाते-सितम्बर 2017 की स्थिति के अनुसार 30.3 करोड़ लाभार्थी

ई गवर्नेंस

- आधार – विश्व की सबसे बड़ी बायोमीट्रिक पहचान प्रणाली। 118 करोड़ आधार कार्ड जारी किए गए
- सरकारी ई-मार्केट प्लेस खरीद में पारदर्शिता लाया है

बेनामी अधिनियम

- 2016 के संशोधन के बाद बेनामी संपत्ति पता लगने के मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि।

मुक्ति 4: आतंकवाद मुक्त भारत (1/2)

वामपंथी उग्रवाद से आम नागरिकों की मृत्यु

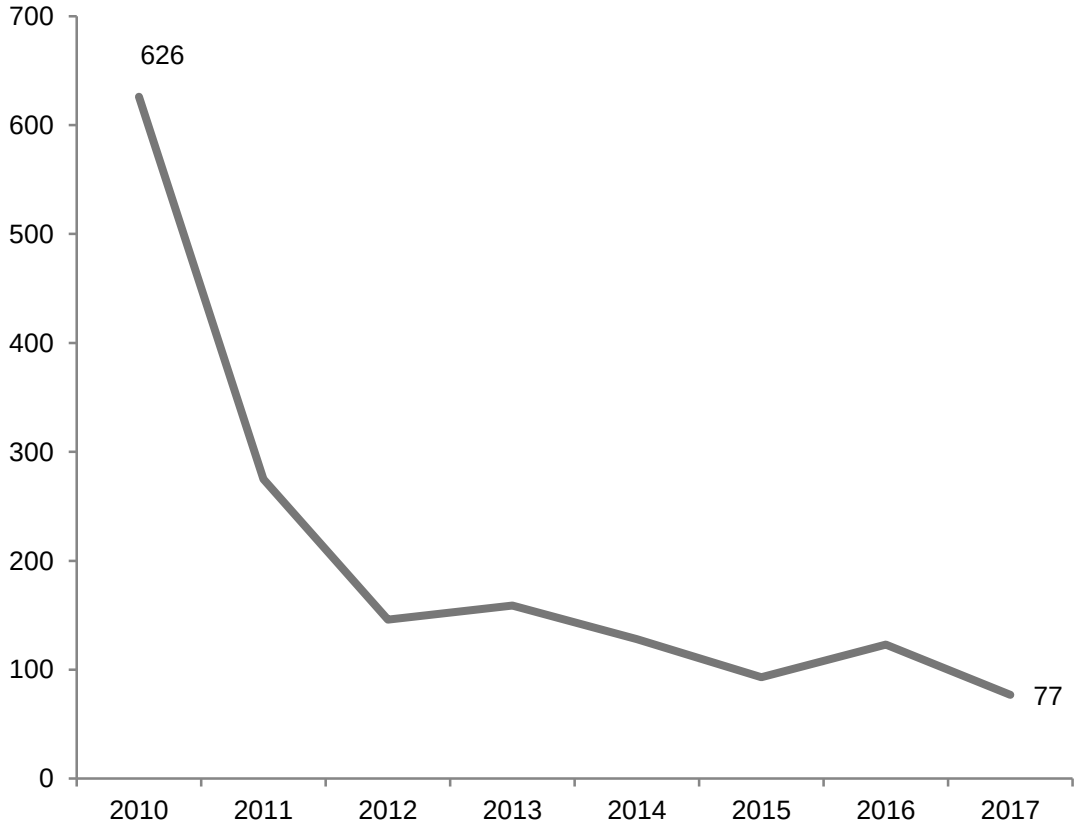

पूर्वोत्तर में आतंकी हिंसा दो दशकों में सबसे कम

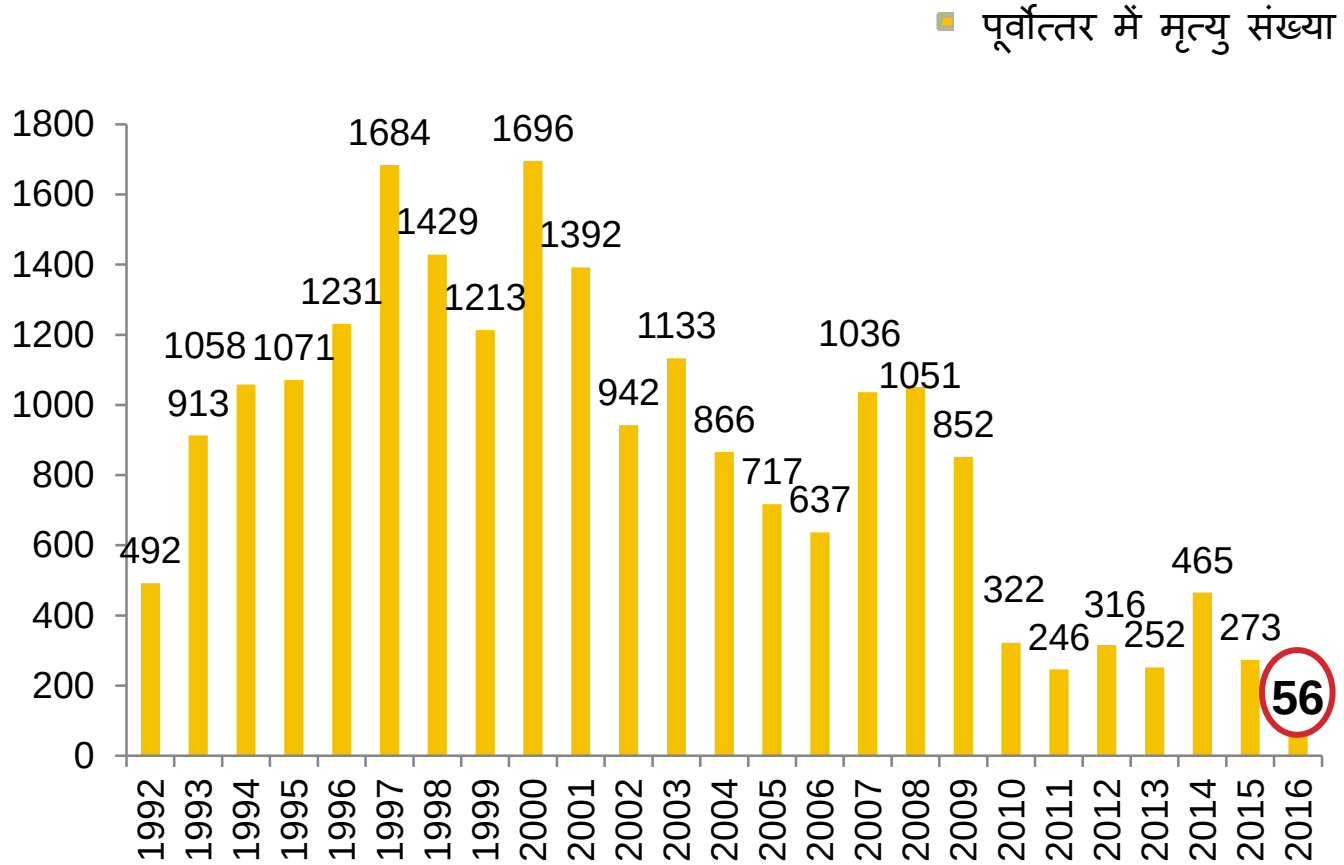

आतंकवाद मुक्त भारत (2/2)

"पुलिस बलों के आधुनिकीकरण" की अम्ब्रैला योजना

2/5 निधियन एलडब्ल्यूई, जम्मू और कश्मीर एवं पूर्वोत्तर को समर्पित

पाकिस्तान को अलग-थलग करने के लिए वैश्विक और क्षेत्रीय स्तरों पर विकास एजेंडा एवं सॉफ्टपावर का सदुपयोग

100 पिछड़े जिलों के लिए समर्पित कार्यक्रम से आंतरिक और सीमा-पार सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा

आतंकवाद को नियंत्रित करने और उनकी क्षमताओं को कमजोर करने के लिए विदेश और भारत में कार्यवाही करी

मुक्ति 5: जातिवाद मुक्त भारत

- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में गरीबी दर में कमी और साक्षरता दरों में वृद्धि परंतु कुछ संकेतकों के संबंध में प्रगति धीमी है

- *प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई), राष्ट्रीय अ.जा./अ.ज.जा. हब, अपग्रेडेशन ऑफ मेरिट ऑफ एससी स्टूडेंट्स*

- पीएमएजीवाई के तहत चयनित सभी ग्रामों को 2022 तक आदर्श ग्राम का दर्जा मिल जाना चाहिए

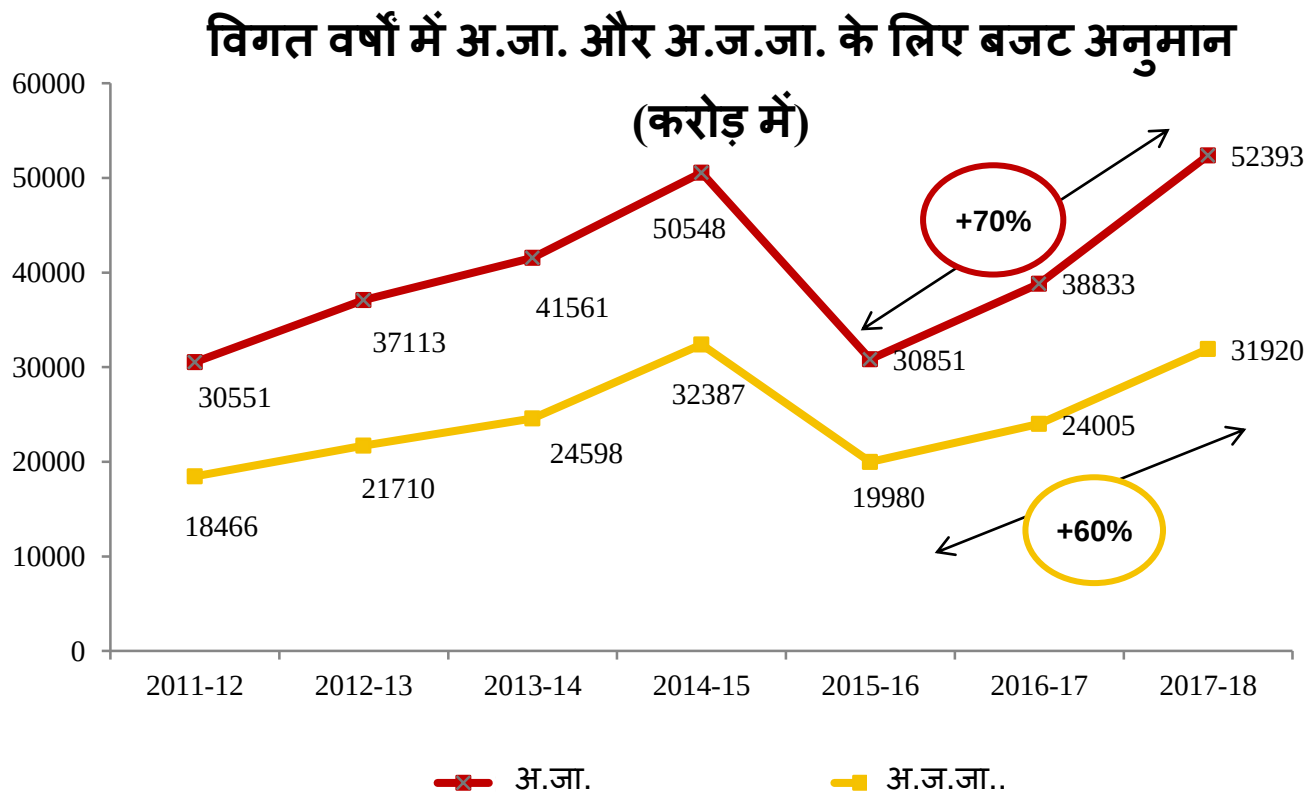

मुक्ति 6: साम्प्रदायिकता मुक्त भारत

- भारत शांति, एकता और सद्भावना के लिए प्रतिबद्ध है
- तुष्टिकरण के बिना सशक्तिकरण न कि हकदारी
- *नई मंजिल, नई रोशनी, स्टैंड-अप इंडिया, बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति, सीखो और कमाओ, पढ़ो परदेस, प्रोग्रेस पंचायत, हुनर हाट*
- ऐसे सांप्रयदायिकतावादी कार्यकलापों पर दस वर्षों के लिए पाबंदी लगा दें, हम एक ऐसे समाज की ओर आगे बढ़ें जो ऐसे तनावों से मुक्त हो – प्रधान मंत्री

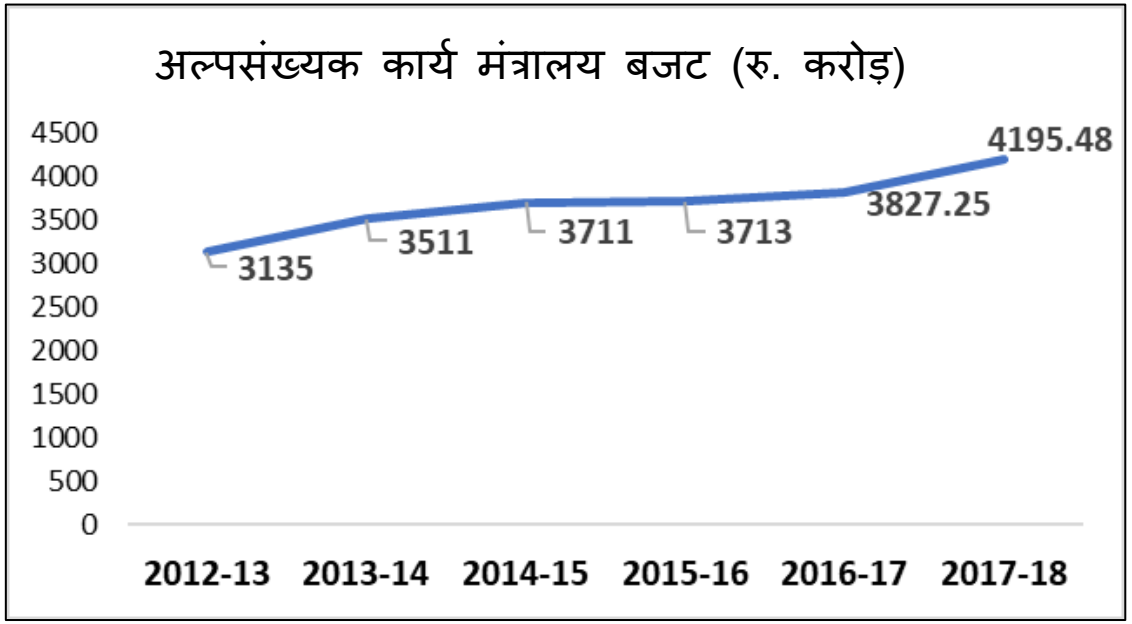

अल्पसंख्यकों के मामले में गत तीन वर्षों की उपलब्धियां (मई 2017 की स्थिति के अनुसार)

1102 भवनों का निर्माण

2090 स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण

47,986 पक्के मकानों का निर्माण

1,38,426 छात्राओं में 166 करोड़ रु. वितरित किए गए

भारत : एक नई सोच

महात्मा गांधी: "मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारों ओर से बंद हो और मेरी खिड़कियां भी बंद हों। मैं चाहता हूं कि सभी जगह की संस्कृति मेरे घर में स्वतंत्रतापूर्वक प्रवेश कर सके। परंतु मैं यह नहीं चाहता कि इनमें से कोई भी मुझ पर हावी हो।"

- *अहिंसा परमो धर्मः* - अहिंसा परम धर्म है।
- *एकम सदः विप्राः बहुधाः वदन्ति* प्रभु एक ही है, विद्वान अनेक प्रकार से इसे बताते हैं।
- *वसुधैव कुटुम्बकम्* - सम्पूर्ण धरती एक परिवार है।
- *सर्व पंथ समभाव* - सर्व धर्म में समान भाव है।
- *सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः* - सभी प्राणी सुखी हो, सभी निरोगी हो
- *वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीड परायी जाणे रे* - वैष्णव जन (सज्जन पुरुष) वो है जो दूसरे की पीड़ा समझता है।
- *यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः* – जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं।

भावी राह

चौथी औद्योगिक क्रांति: अंगीकार अनिवार्य

उद्योग 4.0

- औद्योगिकोत्तर समाज
- बिग डेटा- ठोस आधार पर नीति निर्माण और आकलन

स्वचलन/रोबोटिक्स

- श्रम बाजार के ढांचे में परिवर्तन और उत्पादकता में बढ़ोत्तरी

कृत्रिम बुद्धि, इंटरनेट ऑफ थिंग्स

- मशीन द्वारा सामान्य एवं विशिष्ट श्रम का विस्थापन

ब्लॉकचेन

- वित्तीय लेनदेनों की गति, निजता और मात्रा ब्लॉकचेन से प्रभावित होगी

वैश्विक प्रशासन के गौरवशाली मंच पर भारत

बहुध्रुवीयताः उभरती व्यवस्था

- संयुक्त राष्ट्र की पुनर्कल्पना
- वैकल्पिक वैश्विक मंचों (जी 20, ब्रिक्स, अंतरराष्ट्रीय सोलर एलाइंस) में भारत के नेतृत्व की संभावना
- अंतरराष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तनशील स्थिति
- बदलती वैश्विक वित्त व्यवस्थाः विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से एआईआईबी तथा एनडीबी तक
- आर्थिक केंद्र एशिया की ओर उन्मुखः 2050 में वैश्विक जीडीपी में एशिया का हिस्सा लगभग 50% से अधिक, जो फिलहाल लगभग 25% है

लोकतांत्रिक लाभ

सहकारितापूर्ण संघवाद
(Co-operative Federalism)

- मुख्यमंत्रियों के उप-समूह केंद्रीय नीतियों पर सिफारिशें कर रहे हैं
- जीएसटी काउनसिल
- राज्यों को अधिक धन अंतरण
- अंतर-मंत्रालय समितियां तथा टास्क-फोर्स

प्रतिस्पर्धी संघवाद
(Competitive Federalism)

- राज्यों में सर्वोच्च स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा
- केंद्र विभिन्न सार्वजनिक सूचकांकों के माध्यम से विभिन्न मानदंडों पर प्रतिस्पर्धा का माहौल बना रहा है जिससे इनपुट की तुलना में परिणाम की ओर विशेष ध्यानाकर्षण हुआ
- चुनौती पद्धतिः राज्य केंद्रीय परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं

नीति आयोग लोकतांत्रिक लाभ के एक साधन के रूप में विकसित हुआ है

गवर्नेंस के नए प्रतिमान

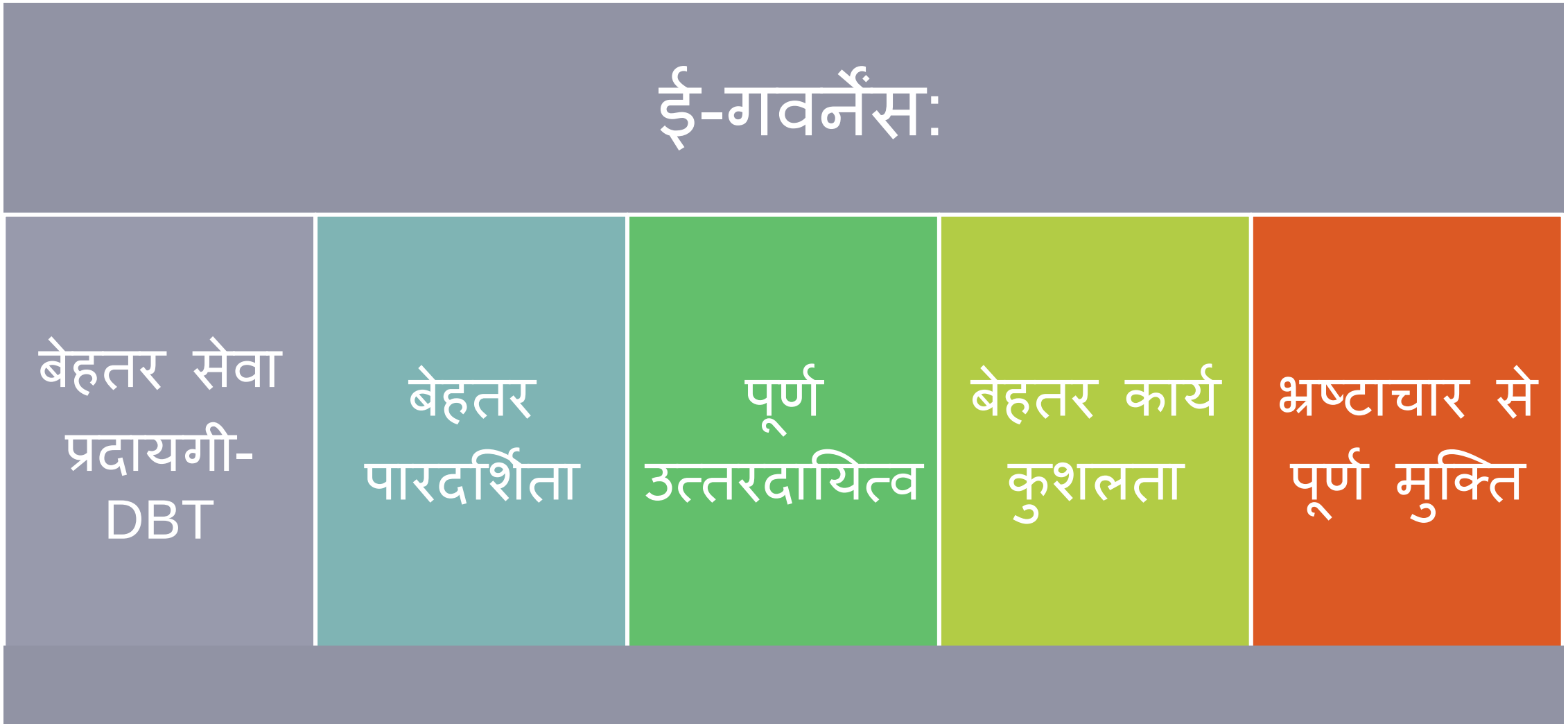

पीपीपी से पीपीपीपी तक

- भारत परिवर्तन का काम अकेले सरकार नहीं कर सकती
- सरकार को माई-बाप मानने (उपनिवेशवाद, सामंतवाद और समाजवाद से उपजी धारणा) की मानसिकता छोड़ें
- गतिशील उद्यमिता के लिए स्थान और पारितंत्र (रोज़गार चाहने वाले की जगह रोज़गार दे सकने वाले) सृजित करें
- हकदारी से सशक्तिकरण तक
- सार्वजनिक-निजी-वैयक्तिक साझेदारी की ओर

2047: सर्वश्रेष्ठ भारत, जगतगुरु भारत

- अभी से लेकर 2047 तक 8% की वार्षिक वृद्धि दर के अनुमान से, भारत विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में होगा।
- स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण को पूरा करना:
- ...व्यवस्था ऐसी हो कि सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर लोगों को भी लाभ मिले।
- ....जहां उदारता, शुचिता, शांति और इन सबसे बढ़कर आत्ममंथन और आध्यात्मिकता का सर्वोच्च शिखर अगर कहीं है, तो भारत में ही है।
- हर देश किसी न किसी संदेश, कोई न कोई ध्येय को लेकर चलता है। भारत का लक्ष्य मानवता को राह दिखाना रहा है।

धन्यवाद